



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2019/फाल्गुन 15, 1940

No. 159]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2019/PHALGUNA 15, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2019

सं. 1/2019-सेवा कर

सा.का.नि. 179(अ).— केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 1 जुलाई, 2012 से प्रारंभ होने वाली और 29 फरवरी, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), किसी ऐसी प्रथा के अनुसार, जो साधारणतया प्रचलित थी, राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रमाणित कौशल या व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अधीन प्रशिक्षण प्रदाताओं (प्रशिक्षण कार्यान्वयन अभिकरणों) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं पर सेवा कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया था और यह सेवा उक्त अवधि में सेवा कर के लिए दायी थी, जो उक्त प्रथा के अनुसार संदत्त नहीं किया जा रहा था।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 83 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ग और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 174 की उपधारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के प्रवृत्त होने से पहले की गई या लोप की गई बातों के संबंध में यह निदेश देती है कि उक्त अवधि में, उक्त प्रथा के कारण, राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रमाणित कौशल या व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अधीन प्रशिक्षण प्रदाताओं (प्रशिक्षण कार्यान्वयन अभिकरणों) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सेवाओं पर वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 66ख के अधीन संदेय सेवा कर संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

[फा. सं. 137/14/2018-सेवा कर]

डा. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th March, 2019

No. 1/2019-Service Tax

G.S.R. 179(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that in the period commencing on and from the 1st day of July, 2012 and ending with the 29th day of February, 2016 (hereinafter referred to as the said period), according to a practice that was generally prevalent, there was non-levy of service tax, on the services provided by training providers (project implementation agencies) under the Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana under the Ministry of Rural Development by way of offering skill or vocational training courses certified by the National Council for Vocational Training, and this service was liable to service tax, in the said period, which was not being paid according to the said practice.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with section 83 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), and clause (e) of sub-section (2) of section 174 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), in respect of things done or omitted to be done before the coming into force of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby directs that the service tax payable under section 66B of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), on the services provided by training providers (project implementation agencies) under the Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana under the Ministry of Rural Development by way of offering skill or vocational training courses certified by the National Council for Vocational Training, in the said period, but for the said practice, shall not be required to be paid.

[F. No. 137/14/2018-Service Tax]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.